उपभोक्ता मामले, खाना और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाना और सार्वजनिक वितरण विभाग)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2015/MAGHA 1, 1936

उपभोक्ता मामले, खाना और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाना और सार्वजनिक वितरण विभाग)
प्राधिकार से प्रकाशित

नई दिल्ली, 21 जानवरी, 2015

साक्षरित 48(अ)—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय खाना सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा 8 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (म) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात निःसंशय नियम बनायी है, अतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाना सुरक्षा भंडा नियम, 2015 है।
(2) ये राज्यपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएँ—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(अ) "अधिनियम " से राष्ट्रीय खाना सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) अभिवृद्धि है;
(ब) "नोडल अधिकारी " से अधिनियम की धारा 14 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामित होने वाले अधिकारी अभिवृद्धि है;
(ग) "हूकडार व्यक्ति " से राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अधीन उस रूप में पहुंचाने गए पात्र गृहस्थों से संबंध रखने वाला और साइड राशनकार रचना वाला, कोई व्यक्ति अभिवृद्धि है;
(घ) शब्द और वर्ग, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, का क्रमश: वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है।

3. खाद्यादि के आबंटन के लिए समय-सीमा—केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों सार्वजनिक वितरण प्रशासी (विनियम) आदेश, 2001 में या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए अन्य आदेशों में उपभोग समय सीमा का खाद्यादि के आबंटन तथा अधिनियम के अधीन हूकडार व्यक्तियों को इस्तेमाल उपलब्ध कराने के लिए पालन करेंगी।

294 GI/2015
4. बाधाओं की आपूर्ति न होने की वजह में बाह्य सुरुचि भले का संदाय—(1) नोडल अधिकारी प्रत्येक मास के अंत में और प्रत्येक उचित दर दुकान का अधिनियम के अधीन उनकी हकदारी के अनुसार प्रत्येक उचित दर दुकान के अधीन आने वाले हकदार व्यक्तियों को बाधाओं के प्रदाय की प्राप्तित का सराहन करेगा;
   (2) नोडल अधिकारी किसी हकदार व्यक्ति को बाधाओं की हकदार मात्रा की आपूर्ति न लिए जाने के कारणों को लेखबद ढेखेगा;
   (3) नोडल अधिकारी प्रत्येक मास में जहां उचित दर दुकान में बाधाओं की अनुपस्थित या किसी अपरिहार्य कारणों से हुकदार बाधाओं की मात्रा की आपूर्ति न होने के प्रत्येक मास में हकदार व्यक्ति को बाह्य सुरुचि भले के संदाय का सुनिश्चित करेगा;
   (4) नोडल अधिकारी, जैसा बाधाओं की किसी उचित दर दुकान द्वारा जान-वृद्धि कर इमानदार नहीं की गई है, वहाँ जिला लिखायत निवारण अधिकारी के पास सुरुत लिखायत रजिस्टर करेगा।

5. आपूर्ति की प्राप्तित का सराहन—राज्य सरकार हर वर्ष अवसर का उपलब्धता के अधीन रहते हुए प्रत्येक उचित दर दुकान के संबंध में निम्नस्थित को करने और अभिलिखित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विभिन्नें का भाग राय करेगी और इसे व्यविधि की लोक दीर्घ संख्या में रखेगी—
   (i) मास के अंत में बाधाओं के उद्धरण की प्राप्तित का सराहन;
   (ii) उद्धरण के कारणन, यदि कोई हो।

6. बाह्य सुरुचि भले की संगठना—हकदार व्यक्तियों को अनुपशव बाह्य सुरुचि भले की रकम की संगठना उस विधि का संबंध के लिए सुरुचि बाधाओं के मूलभूत संचयन में सुधार का 1.25 गुणा और अधिनियम का अनुपूर्ति-1 में विनिर्देश कीमतों के बीच अंतर की आपूर्ति की गई मात्रा से गुणा करके की जाएगी।

7. अवश्य जिसके भीतर बाह्य सुरुचि भले का संबंध किया जाना है—नोडल अधिकारी उस मास जिसमें आपूर्ति नहीं की गई है के परिवारी मात्र के तीसरे संपत्त के अंत के बाह्य सुरुचि भले के संदाय का सुनिश्चित करेगा।

8. बाह्य सुरुचि भले के संदाय का विपक्ष—(1) राज्य सरकार हकदार व्यक्तियों को बैंक खातों के माध्यम से बाह्य सुरुचि भले के निर्वाचन करेगी।
   (2) यदि किसी हकदार व्यक्ति ने बैंक खाता नहीं बोला है, तो ऐसे व्यक्ति को बाह्य सुरुचि भले का आर्थिक संदाय नकद दिया जाएगा।

9. बाह्य सुरुचि भले जब संबंध नहीं है—बाह्य सुरुचि भला किसी हकदार व्यक्ति को संबंध नहीं होगा जो मास के दीर्घ में उचित दर दुकान पर नहीं जाता है।

10. नोडल अधिकारी द्वारा संचित रिपोर्ट—नोडल अधिकारी नियम 4 में विनिर्देश बाधाओं की आपूर्ति की प्राप्तित के सामाजिक संवाद के आधार पर जिला विकास केंद्र या इस प्रवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को निवारण के मास के परिवारी मात्र के पंद्रह हर तक हकदार व्यक्तियों को बाधाओं की आपूर्ति के किये जाने वाले मामलों के उद्धरण करने के लिए उनके कर्मचारियों के साथ और जहाँ आवश्यक हो, ती की गई उपचारकारी कार्यालय की एक संचित रिपोर्ट प्रत्युक्त करेगा।

11. बाधाओं के क्वालिटी के संबंध में विकास—बाधाओं के क्वालिटी के संबंध में कोई विकास, विकासवत्ता द्वारा जिला विकास निवारण अधिकारी की विशेषता उसकी विकास तदानुसार करने के लिए की जाएगी, इसकी वजह और इस पर विशेषता जिला विकास निवारण अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा पंद्रह हर दिन से आर्थिक अवधि के भीतर किया जाएगा।
12. एक मास से अधिक हृदयारी का वितरण—राज्य सरकारों द्वारा एक समय में एक मास से अधिक की हृदयारी की आपूर्ति की प्रति का अनुशासन करने की दशा में हृदयारी व्यक्तियों की ऐसी हृदयारीयों की आपूर्ति के सत्यापन के लिए सम्भवित प्रबंध संबंधित राज्य सरकार द्वारा किए जाएंगे ताकि हृदयारी के अनुसार बाह्यातों के वितरण या हृदयारी बाह्यातों की मात्रा की आपूर्ति के लिए जाने वाले मामलों की दशा में हृदयारी व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा भारों के संदर्भ में सुनिश्चित की जा सकें।

13. राज्य सरकारों की निदेश जारी करने की क्षमता—राज्य सरकारें, यदि आवश्यक समय, तो इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेंगी जो वह उचित राजस्वी हो।

[फ. सं. 15-59/2013-एनएफएसए०]
वीफेक कुमार, संबंध सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Deartment of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION
New Delhi, the 21st January, 2015.

G.S.R. 48(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 39 read with Section 8 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013), the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Food Security Allowance Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
(a) "Act" means the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013);
(b) "nodal officer" means an officer designated as such by the State Government under section 14 of the Act;
(c) "entitled person" means a person belonging to eligible households identified as such under the Act by the State Government and in possession of a valid ration card;
(2) words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Time limits for allocation of foodgrains.**—The Central Government and the State Governments shall adhere to the time limits provided in the Public Distribution System (Control) Order, 2001 or any other orders issued from time to time by Central Government, for allocation of foodgrains and making them available for distribution to the persons entitled under the Act.

4. **Payment of food security allowance in cases of non-supply of foodgrains.**—(1) The nodal officer shall verify, at the end of every month and at each fair price shop, the status of supply of foodgrains to the entitled persons covered under each fair price shop, as per their entitlement under the Act.
(2) The nodal officer shall record in writing, the reasons for non-supply of entitled quantity of foodgrains to any entitled person.
(3) The nodal officer shall ensure payment of food security allowance to the entitled person in every case where entitled quantity of foodgrains has not been supplied due to non-availability of foodgrains at the fair price shop or for any unforeseen reasons.
(4) The nodal officer shall register a complaint with the District Grievance Redressal Officer forthwith where foodgrains have not been supplied due to any willful lapse of any fair price shop dealer.
5. Verification of status of supply.—The State Government shall use electronic methods, subject to availability of adequate infrastructure, for carrying out and recording the—

(i) month-end verification of status of distribution of foodgrains; and

(ii) reasons for non-distribution, if any, in respect of each fair price shop and place such details in the public domain.

6. Computation of food security allowance.—The amount of food security allowance admissible to entitled persons shall be computed by multiplying the difference between the 1.25 times the minimum support price of the relevant foodgrains for that marketing season and the prices specified in Schedule I to the Act, with the quantity of non-supply.

7. Period within which food security allowance to be paid.—The nodal officer shall ensure the payment of food security allowance by the end of the third week of the month following the month in which the non-supply occurred.

8. Mode of payment of food security allowance.—(1) The State Government shall ensure the payment of food security allowance to the entitled persons through bank accounts.

(2) If any entitled person has not opened a bank account, the initial payment of food security allowance to such person shall be made by cash:

Provided that the nodal officer shall ensure that a bank account is opened by such person within one month from the date of initial payment of the food security allowance.

9. Food security allowance when not payable.—The Food security allowance shall not be payable to an entitled person who does not visit the fair price shop to claim his entitlement during the month:

Provided that the nodal officer may exempt a person from visiting the fair price shop and claiming his entitlement, for reasons to be recorded in writing:

Provided further that the food security allowance shall not be payable to an entitled person who refuses to claim his entitlement on the ground of quality of foodgrains or on such other grounds.

10. Summary report by Nodal Officer.—The nodal officer shall, based on monthly verification of status of supply of foodgrains, specified in rule 4, submit a summary report to the District Magistrate, or any other officer authorised by the State Government for this purpose, by fifteenth day of the month following the month of distribution, indicating the cases of non-supply of foodgrains to the entitled persons, along with reasons and the remedial measure taken, wherever necessary.

11. Complaint regarding quality of foodgrains.—Any complaint relating to quality of foodgrains shall be made by the complainant to the District Grievance Redressal Officer in writing seeking redressal of his complaint, which shall be inquired into and decided by the District Grievance Redressal Officer or any other officer authorised by the State Government within a period not exceeding fifteen days.

12. Distribution of more than one month entitlement.—Where the State Governments follow the practice of supply of more than one month's entitlement at a time, appropriate arrangements for verification of supply of such entitlements to the entitled persons shall be undertaken by the concerned State Government so as to ensure distribution of foodgrains as per the entitlements or payment of food security allowance to eligible persons in case of non-supply of entitled quantity of foodgrains.

13. State Governments competent to issue directions.—The State Governments, if considered necessary, may issue such directions for the implementation of these rules, as deemed fit.

[F. No. 15-59/2013-NFSA]

DEEPAK KUMAR, Jt. Secy.